सहकारी सामहिक आवास समितियों को करीब 1248 एकड़ भूमि आबंटित की है। द्वारका चरण-I और II तथा नरेला में करीब 400 सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि आबंटित करने का प्रस्ताव है। शेष समितियों के लिए भूमि की अनुमानित आवश्यकता करीब 900 हैक्टेयर होगी। इन समितियों को भूमि का आबंटन भूमि का और अधिग्रहण और विकास करने के पश्चात् ही किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए इस समय कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बनाई जा सकती है।

Allotment of Houses/Plots by D.D.A.

1245. SARDAR JAGJIT SINGH AURORA:

SHRI RANJIT SINGH:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of applicants are registered with the Delhi Development Authority for residential plots and residential units etc.;

(b) if so, what is the number of applicants who were not allotted plots or residential units till December 1990, and whether Government have any time-bound programme to meet the needs of the remaining registered applicants; and

(c) if so, the details in this regard and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DAULAT RAM SARAN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) 91,448 registrants for flats and 45,856 registrants for plots were awaiting allotment till December, 1990. All these registrants are likely to be allotted flats/plots by the end of 8th Five Year Plan.

दिल्ली में सहकारी आवास समितियों को भूमि का आवंटन

1246. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में लगभग 320 सहकारी आवास समितियों को भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों को भूमि का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा तथा उन्हें भूमि का कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन समितियों को दी जाने वाली भूमि की कीमत अभी 975 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गयी है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1987 में पप्पनकलां की भूमि की कीमत 425 रुपये प्रति वर्ग मीटर आंकी गयी थी और इस दर पर डी० डी०ए० द्वारा कितनी भूमि आवंटित की गयी थी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका चरण-I तथा II और नरेला में लगभग 400 सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटित करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

(ख) प्रीमियम की अदायगी सहित कोडल औपचारिकताओं के पूरा होने पर तथा समितियों की परस्पर-वरिष्ठता नियत करने के लिये निर्धारित किये गये मानदंड को चुनौती देने संबंधी उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं के निर्णय की शर्त पर।

(ग) द्वारका में समितियों को भूमि के आवंटन के लिये चालू दर 975 रुपये प्रति वर्ग मीटर नियत की गई है।

(घ) 1-9-87 से 31-8-88 तक दक्षिण और केन्द्रीय दिल्ली क्षेत्र के लिये भूमि की वैध दरें 450 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी। तथापि, इस दर पर पप्पन कलां/द्वारका में कोई भूमि आबंटित नहीं की गई है।

Prices of Vanaspati and Edible Oils

1247. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL:
SHRI DHULESHWAR MEENA:
MISS SAROJ KHAPARDE:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item which appeared in the Hindustan Times, Dated 8-2-91 under the caption 'Edible Oil prices up by 12 p.c.'

(b) if so, whether Government propose to direct edible oil manufacturers to bring down the prices of their products;

(c) if so, by when and if not, the reasons therefor; and

(d) what other steps Government propose to take against edible oil manufacturers in the country?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAO BIRENDRA SINGH): (a) to (c) Yes, Sir. Minister for Food and Civil Supplies called a meeting on 15-2-91 to discuss the price rise/availability of vanaspati. He appealed to vanaspati Associations to voluntarily reduce the prices so as to give effective relief to the consumers. The Industry's response, however, was not encouraging. They wrote back subsequently on 20-2-1991 to suggest adjusting downwards of prices of 15 kg. vanaspati tin by Rs. 15/- when prices of raw oils had already softened since 15-2-1991.

(d) Government's main efforts is to bring down the prices of edible oils in general, by import for Public Distribution System and increased availability of substitutes. The prices of vanaspati are dependent on prices of raw oils.

रेलवे में बिजली के उपयोग में किफायत

1248. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा
श्री रणजीत सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रेलवे में बिजली की खपत में किफायत करने के लिये गत तीन वर्षों से एक योजना कार्यान्वित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि 1986–87 से प्रति वर्ष विद्युत ऊर्जा के उपयोग में किफायत की गई है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने प्रतिशत बिजली की बचत की गई है और इस वर्ष कितनी बिजली की बचत की जायेगी और क्या सरकार ने आने वाले वर्ष में विद्युत ऊर्जा की बचत करने के लिये लक्ष्य निर्धारित किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरन दास) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

यमुनानदी परियोजना

1249. **श्री रणजीत सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जनवरी, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "यमुना रिवर प्रोजेक्ट रीव्यू" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में यमुना नदी के किनारे विकास के लिये बनाई गई योजना के कार्यान्वयन के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है और इस परियोजना पर कब तक कार्य प्रारंभ किये जाने की संभावना है ?